बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है; श्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रौर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अंतर्गत मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण श्रौर शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कानूनी श्रौर संवैधानिक पहलुश्रों सहित विभिन्न दृष्टि-कोणों से गहराई से जांच करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Expenditure on forces in Punjab and J and K

1029. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the expenditure incurred by Government on deployment of Para Military Forces in Punjab and Kashmir since 1980?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में कानून श्रौर व्यवस्था की स्थिति

1030. **श्रीमती रत्न कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने मध्य प्रदेश में कानून श्रौर व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में हाल में राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; श्रौर

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रौर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) श्री श्रर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस (श्राई) के कुछ सदस्यों ने जनवरी, 1992 में भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिन्दुश्रों के पवित्र पूजा स्थलों को तोड़े जाने का श्रारोप लगाया गया है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में उपयुक्त ज्ञापन में दिए गए श्रारोपों का खंडन किया है।

Amendment to official Secrets Act

1031. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the "Times of India' dated the 2nd February, 1992 regarding amendment to the Official Secrets Act for providing full information to the journalists; land

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOBS (a) Yes, Madam.

(b) Inter-Ministerial Task Force was set up to go into the entire question regarding Right to Information etc., which has since submitted its Report. Its recommendations reflect on the one hand, the need for a more purposeful information dissemination system, and OH the other, a close and comprehensive look on the issues relating *to* security classification and privacy. In view of the importance and complexity of the subject, formulation of definite views on the issues involved in the matter, including amendments to Official Secrets Act, 1923, would necessarily take time